लोक निर्माण(भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने कल सदन की गरिमा को भारी ठेस पहुंचाई। लोकतांत्रिक मर्यादाओं की कल धज्जियां उड़ाई गई। ये लोग हाउस की वैल में आ गए। हाउस को एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार एडजर्न करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आपने बार बार इनको बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं पूरे सदन की तरफ से आपको आपकी विनम्रता के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने रिपीटिडली हाउस को एडजर्न किया, आपने उनको उनकी सारी उदंडता के बावजूद अपने चैम्बर में आकर अपनी बात रखने का मौका दिया । अध्यक्ष महोदय, काम रोको प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी संसद में भी लेकर आई थी। वहां पर भी स्पीकर साहिबा ने उस काम रोको प्रस्ताव को एक शोर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में कंवर्ट किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि वे इस समय सदन में मौजूद हैं। इनकी पार्टी ने संसद में जो काम रोको प्रस्ताव दिया था वहां की हमारी अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार जी ने उस काम रोको प्रस्ताव को शोर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में कंवर्ट किया। आपके नेताओं ने उसको स्वीकार किया और उस पर बकायदा चर्चा हुई । अध्यक्ष महोदय, आपने कल काम रोको प्रस्ताव को कालिंग अटैंशन मोशन में कंवर्ट करके आज के लिए रखा । प्राइस राईज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूरा देश इस मंहगाई के मुद्दे को लेकर चिंतित है। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि जो काल अटैंशन मोशन एडमिट किया है उस पर भाजपा के साथी भी और लोकदल के साथी भी जितने चाहे सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहकर और दरियादिली दिखाई कि आप उन्हें पूरा समय प्राइस राइस के ऊपर चर्चा के लिए देंगे और गवर्नर एड्रैस पर चर्चा करने के लिए पूरा समय देंगे । अध्यक्ष महोदय, आपने यह कह कर और दरियादिली दिखाई कि आप बजट पर चाहे जितना बोल सकते हैं उतना बोल लेना, तो ऐसे में डिस्कशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी परन्तु अगर कोई प्रिमैडीटेटिड माइंड यह बनाकर आए कि हमने सदन को चलने नहीं देना तो यह ठीक नहीं है। कल हमने सदन में देखा कि किस प्रकार से संसदीय कार्य प्रणाली को तहस-नहस किया गया । स्पीकर के पोडियम तक कल किस प्रकार लोग आए और कागज दिखाकर स्पीकर की तरफ किस प्रकार इशारे किए गए । जिस प्रकार से अभद्र भाषा का इस सदन में इस्तेमाल किया गया, और जिस प्रकार से यहां नारेबाजी की गई, यह सदन की गरिमा की परिपाटी नहीं है। हमारे सम्मानित साथी कम से कम यहां जो लिखा है उसको पढ़ लेते । प्राइस राइस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि हमारे साथी हाउस में मौजूद नहीं हैं लेकिन हमारी बहन जी यहां मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ तथ्य इस सदन के नोटिस में अवश्य लाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि महंगाई जो है वह देश की सरकार के लिए और प्रदेश की सरकार के लिए चिंता का विषय है। हमने हरियाणा प्रांत के अंदर और पूरे देश में कई कारगर कदम महंगाई के बारे में उठाये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश पूरे देश में खाद्यान के भण्डार को भरने वाला प्रदेश है। आज के दिन देश खाद्यान के मामले में पूर्णत: स्वावलंबी हुआ है तो उसमें हरियाणा प्रदेश का विशेष योगदान है। वर्ष 2008 में विश्व स्तर पर जब खाद्यानों की उपलब्धता में

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

कमी आ रही थी उस समय हरियाणा में खाद्यानों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई । रबी की फसल में 2008 में देश में केवल 102 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन किया गया जिसमें चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 52 लाख मीट्रिक टन का योगदान हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा के गरीब मजदूर और हरिजन भाईयों ने केंद्रीय पुल में दिया ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पूरे देश की कल्याणकारी योजनाएं सुचारू रूप से चलें । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से खरीफ की फसल में 2008 में हरियाणा के किसानों ने 49 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया तथा हमारे प्रांत ने केंद्रीय पूल में 14.23 लाख मीट्रिक टन चावल का योगदान दिया ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई व्यक्ति भूखा न रहे। इसके अतिरिक्त तीन लाख मीट्रिक टन बाजरे का योगदान भी हमने केन्द्रीय पूल में दिया। सर, जो यह मौजूदा साल 2009 चल रहा है इसमें भी रबी की फसल में केन्द्रीय पूल हेतू 69 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक के गेहूं की खरीद केवल हरियाणा ने की है । यह राज्य के लिए खरीद का एक नया कीर्तिमान भी है। गत वर्ष सितम्बर, 2009 के मध्य में केन्द्रीय सरकार ने विशेष अनुसंसा हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की कि खरीफ वर्ष 2009-10 में अधिक से अधिक चावल का योगदान हमारा प्रदेश केन्द्रीय पूल में दे क्योंकि पूरे देश में सूखे की स्थिति है । अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2009 में सूखे जैसी स्थिति के बावजूद हरियाणा सरकार ने इस अप्रत्याशित चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया तथा धान की रोपाई हेतू विशेष तौर पर बिजली और पानी का प्रबंध किया । जिसके परिणामस्वरूप विषम परिस्थितियों में भी हरियाणा में धान का रिकार्ड उत्पादन हुआ तथा पिछले वर्ष के मुताबिक इस साल 45 प्रतिशत धान की अधिक खरीद हुई । अध्यक्ष महोदय, यहां यह बताना भी उचित है कि सीजन के शुरूआत में हमने केन्द्र सरकार को आश्वासन दिया था कि हम 13.90 लाख मीट्रिक टन चावल का योगदान केन्द्रीय पूल में देंगे। हमें गर्व है कि हम इस लक्ष्य को 34 प्रतिशत बढ़ाकर देंगे ताकि पूरे देश के खाद्यान भण्डार पूरे हो सकें । इस वर्ष हमारा केन्द्रीय पूल में चावल का योगदान 18.60 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि खाद्यान के उत्पादन में हम देश के सबसे अग्रणी राज्य हैं । इसके अतिरिक्त मैं दो-तीन बातें सदन के नोटिस में और लाना चाहूंगा कि हमने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए पूरे राज्य में उच्च स्तरीय कमेटियों का गठन किया है । हरियाणा सरकार ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि काला बाजारी और जमाखोरी की वजह से कीमतें न बढ़ें दिनांक 20 जून, 2008 को गेहूं, चावल, दालें, खाद्य तेल, खाद्य तेल बीजों संबंधी स्टॉक घोषणा आदेश जारी किया है जिसमें उक्त वस्तुओं की निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने पर सरकार को सूचित करने का प्रावधान रखा गया है । इसी प्रकार से 12 अगस्त, 2009 को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से आदेश जारी करते हुए चीनी को भी इन वस्तुओं में शामिल किया गया है। इन आदेशों के पालन हेतू 11 हजार से अधिक डीलरों को हरियाणा सरकार ने चैक किया है तथा कई फर्मों के चालान भी किए गऐ हैं । अध्यक्ष महोदय, चीनी का उत्पादन हमारे प्रदेश में 2010-11 में और ज्यादा हो उसके लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा हमने गन्ने का भाव 210 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अरली वैरायटी का फिक्स किया है और 200 रुपये प्रति क्विंटल लेट वैरायटी का है। हरियाणा पूरे देश में पहला ऐसा प्रांत है जिसने इतना ज्यादा रेट दिया है। स्पीकर सर, हमने यह निर्णय भी लिया है कि जो शूगर केन है उसको लगाने के लिए दो हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सबसिडी किसानों को दी जाये। इस प्रकार का क्रांतिकारी निर्णय लेने वाला भी हरियाणा शायद पूरे देश में पहला प्रान्त होगा। स्पीकर सर, इसके अलावा हमने शूगर केन पर

टेक्नालॉजी मिशन की व्यवस्था भी की है । स्पीकर सर, अगस्त, 2009 में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी 9293 उचित मूल्य की दुकानों की विशेष चैकिंग का निर्णय लिया और इनमें से 7995 दुकानों का हम निरीक्षण भी कर चुके हैं। इनमें से 2018 उचित मूल्य की दुकानों में जहां निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं और कमियां पाई गई वहां पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है । स्पीकर सर, आवश्यक वस्तुओं की दरों की समीक्षा करने के पश्चात् मुख्यमंत्री जी ने 28 जनवरी, 2010 को आवश्यक वस्तुओं की दरों में स्थिरता लाने, कीमतों की वृद्धि को चैक करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गेहूं, चावल, चीनी, दालों; खाद्य तेल और खाद्य तेल बीज़ों में जो स्टॉक की सीमा है वह भी पूर्णतया निर्धारित की। इससे थोक और परचून विक्रेता भी तय सीमा से अधिक उपरोक्त वस्तुओं का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। स्टॉक सीमा को निर्धारित करने के उपरांत 15 फरवरी, 2010 यानि कि गत महीने से हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं । 678 थोक विक्रेताओं, 19 परचून विक्रेताओं का हमने पिछले 15 दिन से अधिक में निरीक्षण भी किया है। स्पीकर सर, राज्य सरकार द्वारा खुला बाज़ार बिक्री योजना के तहत 19522 टन गेहूं नारी निकेतनों, वृद्ध आश्रमों, कुष्ठ रोगी आश्रमों, बाल सुधार गृहों आदि को 1176 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जारी करने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को 6.86 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं दे रहे हैं। स्पीकर सर, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पी०डी०एस० के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को अतिरिक्त तौर पर हम 11.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 31480 टन गेहूं और देंगे। स्पीकर सर, इसके अलावा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर फल और सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाये इसके लिए हरियाणा प्रदेश के 17 जिलों में 85 जगहों पर हमने अपनी मंडी का आयोजन करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने खुला बाज़ार बिक्री योजना के तहत पांच लाख मीट्रिक टन गेहूं जारी किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अगले दो मास में 2 से 3 लाख टन गेहूं तथा चावल खुले बाजार में बेचने का भी निर्णय लिया है। स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से दो बातें और माननीय सदस्यों के नोटिस में लाना चाहूंगा। स्पीकर सर, हमारे जो विपक्ष के लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं उन्होंने कल और शुक्रवार को महंगाई बढ़ने और विशेषकर पेट्रो ग्राईसिज़ के बढ़ने की चर्चा की थी । स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से केवल दो आंकड़े सदन में देना चाहता हूं । स्पीकर सर, केन्द्र की सत्ता से कांग्रेस की सरकार वर्ष 1996 में चली गई थी। 1999 से लेकर अगस्त 2004 तक केन्द्र में एन०डी०ए० की सरकार थी। वर्ष 1996 में जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय डीज़ल का भाव 8.02 रुपये प्रति लीटर था। बाद में जब श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में केन्द्र में एन०डी०ए० सरकार सत्ता में आई तो लोकदल के पांच सांसदों के दम पर सत्ता में आई थी। अगर किसी भी समय ये लोकदल के पांच सदस्य अपना समर्थन वापिस ले लेते तो वह सरकार गिर जाती। उस समय डीज़ल 8.89 रुपये प्रति लीटर यानि 8.90 रुपये प्रति लीटर था। स्पीकर सर, लोकदल के पांच सदस्यों के समर्थन से चलने वाली केन्द्र सरकार ने किसानों के ईंधन डीज़ल की कीमत को 18 बार बढ़ाया। स्पीकर सर, यह मैं केवल आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए बता रहा हूं । जनवरी, 1999 में डीज़ल का भाव 8.89 रुपये प्रति लीटर था। फरवरी, 1999 में इसको बढ़ाकर 9.94 रुपये कर दिया, उसके बाद अप्रैल, 1999 में 10.37 रुपये प्रति लीटर किया, अक्तूबर, 1999 में इसको बढ़ाकर 13.91 रुपये प्रति लीटर कर दिया, जनवरी, 2000 में एन०डी०ए० की सरकार ने 14.04 रुपये प्रति लीटर कर दिया, सितम्बर, 2000 में एन०डी०ए० की तत्कालीन सरकार ने डीज़ल का भाव फिर से बढ़ा कर 16.55 रुपये प्रति लीटर कर दिया, मार्च, 2001 में फिर से डीज़ल का भाव बढ़ाकर 17.06 रुपये प्रति

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

लीटर कर दिया, फिर जनवरी, 2002 में बढ़ाकर 17.09 रुपये प्रति लीटर कर दिया, उसके बाद जून, 2002 में डीजल के रेट को बढ़ाकर 18.23 रुपये प्रति लीटर कर दिया फिर सितम्बर, 2002 में बढ़ाकर 18.68 रुपये प्रति लीटर कर दिया, अक्तूबर, 2002 में 19.63 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया और जनवरी, 2003 में 19.47 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया । इसी प्रकार से फरवरी, 2003 में ही उसको बढ़ा कर 19.84 रुपये कर दिया गया । सितम्बर, 2003 में डीजल के दाम 20.33 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिये गये । दिसम्बर, 2003 में 20.73 तथा जनवरी, 2004 में 21.73 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। मार्च, 2004 में 21.74 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। जून, 2004 में 22.74 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया और अगस्त 2004, में जब इनकी सरकार गई जब इन्होंने आखिरी बार बढ़ाया उस समय डीजल के दाम 24.16 रुपये प्रति लीटर थे । इनकी सरकार ने 18 बार डीजल की कीमतें बढ़ाई थी। 8.02 रुपये प्रति लीटर पर हम डीजल के भाव छोड़ कर गये थे तब केन्द्र में लोकदल के 5 सांसदों के दम पर सरकार चलती थी, उन्होंने डीजल के दाम 24.16 रुपये तक बढ़ाये। अध्यक्ष महोदय, उस 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नैशनल लोकदल की सरकार ने 171.77 परसैंट डीजल की कीमतों में बढ़ौतरी की थी। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मिट्टी के तेल के दाम भी बढ़ाये गये। अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की सरकार 1996 में दिल्ली से गई तो उस समय मिट्टी के तेल की कीमत 2.52 रुपये प्रति लीटर थी। सर, मिट्टी के तेल की जरूरत सबसे ज्यादा हमारी गृहणियों को होती है। जब इनकी सरकार आई तो जनवरी, 1999 में मिट्टी के तेल का भाव 2.52 रुपये प्रति लीटर था। इन्होंने 5 बार मिट्टी के तेल के भाव बढ़ाये । मार्च, 2000 में बीजेपी और इनेलो की सरकार ने मिट्टी के तेल का भाव 5.55 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिया। सितम्बर, 2000 में 8.35 रुपये प्रति लीटर तथा मार्च, 2002 में बढ़ाकर इसको 8.98 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। इसी प्रकार से जून, 2003 में 9.01 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। इस प्रकार से 288 परसैंट इन्होंने मिट्टी के तेल के दाम बढ़ाए। इनकी सरकार गई और श्रीमती सोनिया गाँधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आई तो हमने 5 साल में एक पैसा भी मिट्टी के तेल के भाव नहीं बढ़ाये। इसी प्रकार से रसोई गैस जो गृहणियाँ इस्तेमाल करती हैं, जिस समय हमारी सरकार गई उस समय गैस के सिलेंडर के दाम 119.95 रुपये प्रति सिलेंडर था। जब 1999 में इनकी सरकार आई जो लोकदल के 5 सांसदों के सहारे पर चलती थी, इन्होंने आते ही एक सिलेंडर की कीमत 136 रुपये कर दी। फरवरी, 1999 में ही उसको बढ़ा कर 146 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया। मार्च, 2000 में 196.55 रुपये प्रति सिलेंडर तथा सितम्बर, 2000 में ही 232.25 रुपये प्रति सिलेंडर तक रसोई गैस के दाम बढ़ाये गये। मार्च 2002 में 259.95 रुपये प्रति सिलेंडर तक बढ़ाए। जून, 2004 में इनकी सरकार ने जाने से पहले 261.50 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, 92.35 परसैंट तक इन्होंने रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाये। इसी प्रकार से जब हमारी सरकार गई उस समय पैट्रोल के दाम 21.30 रुपये प्रति लीटर थे और जब इनकी सरकार गई तो इन्होंने उसको 36.81 रुपये प्रति लीटर पर लाकर छोड़ा जो कि 53.76 परसैंट वृद्धि है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी इसलिए सदन से नहीं गये कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया बल्कि वे इसलिए चले गये कि उनके पास इन आँकड़ों का कोई जवाब ही नहीं था । वे कायरता से अपनी पीठ दिखा कर यहाँ से चले गये हैं। न केवल भारतीय जनता पार्टी के साथी ही दौड़ गये बल्कि इंडियन नैशनल लोक दल के साथी भी दौड़ गये। इसी प्रकार से खीकर सर, यूरिया और डी.ए.पी. के

दाम भी बढ़ाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो आँकड़े देकर बैठ जाऊंगा। एक मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप भी एक किसान हैं और इस सदन में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का बहुमत है। जब हमारी कांग्रेस की सरकार 1996 में दिल्ली में गई उस समय यूरिया के 50 किलो के एक बैग का रेट 166 रुपये था और जब 1999 में इनकी सरकार आई उस समय भी 166 रुपये प्रति बैग था। इन्होंने 29 जनवरी, 1999 को आते ही उस बैग का भाव 200 रुपये कर दिया। 29 फरवरी, 2000 को 30 रुपये और बढ़ा कर एक बैग की कीमत 230 रुपये कर दी। इसी प्रकार से 28 फरवरी, 2002 को 241.50 रुपये प्रति बैग कर दिये गये। सितम्बर, 2004 को जब ये गये तो 241.50 रुपये एक बैग की कीमत थी। चौटाला जी किसान का नाम लेकर जो घड़ियाली आँसू बहाते हैं। उन्होंने वाजपेयी जी को या बी०जे०पी० को कभी यह नहीं कहा कि आप यूरिया के बैग के रेट कम कर दो नहीं तो मैं समर्थन वापिस ले लूंगा। पता नहीं, इनकी क्या मजबूरी थी । पांच सांसदों के उपर सरकार चलती थी, क्या यह सच नहीं है। सबको मालूम है कि मेज के नीचे भाजपा से किस प्रकार से गुप्त समझौते चौटाला जी और उनके बेटे किया करते थे। इनके गुप्त समझौते की वजह से चाहे किसान भाड़ में जाएं इसकी चिन्ता इन्हें नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, जो हम यूरिया का भाव 166 पर छोड़कर गए थे उस यूरिया का भाव 241 रुपये इन लोकदल के साथियों के समर्थन वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अध्यक्ष महोदय, 45.48 प्रतिशत यूरिया का रेट बढ़ाया था। डी०ए०पी० जो आप, मैं और इस सदन के अधिकतर सदस्य अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी सरकार गई तो 390 रुपए का रेट 50 किलो के बैग का था। इन्होंने 1999 के अन्दर 390 रुपए से बढ़ाकर 415 रुपए डी०ए०पी० के 50 किलो के थैले का रेट कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, 29 जनवरी, 1999 को फिर रेट बढ़ाया और उसको 445 रुपए कर दिया। उसके बाद 28 फरवरी, 1999 को दोबारा से रेट बढ़ाकर 467 रुपए 50 पैसे कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो रेट बढ़ाए हैं। मैं यह दावे के साथ और जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि केन्द्र में श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार है और सितम्बर, 2004 से लेकर आज तक केन्द्र की सरकार ने एक रुपए भी डी०ए०पी० और यूरिया का नहीं बढ़ाया है। कितना भी भार उनको सहना पड़ा लेकिन सोनिया गांधी जी की सरकार ने रेट नहीं बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यूरिया, डी०ए०पी०, पैट्रोल, डीजल, एल०पी०जी० और कैरोसीन के रेट्स बढ़ाए हैं। आज वे इस सदन से दौड़ गए हैं और वे इसलिए दौड़ गए हैं क्योंकि वे सदन में हमें फेस नहीं कर सकते हैं। उनको मालूम है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली इस देश की सरकार ने क्या क्या कारगर कदम उठाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक आंकड़ा देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा । किसान जब इनके राज में पिस रहा था तब डीजल के भाव इन्होंने 8 रुपए से बढ़ाकर 24 रुपए कर दिए थे, तब इन्होंने गैस के सिलैंडर का भाव 119 रुपए से बढ़ाकर 261 रुपए कर दिया था । तब मिट्टी का तेल 2 रुपए 52 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपए कर दिया था। उस वक्त चौटाला साहब ने उल्टा डीजल और पैट्रोल पर वैट टैक्स लगाकर पैसा इक्ट्ठा करने का काम किया था । अध्यक्ष महोदय, आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं । इनके पांच साल के शासन काल में 1999-2000 से लेकर 2004-05 तक केवल डीजल के ऊपर वैट टैक्स हरियाणा के गरीब किसान और ट्रांसपोर्टरों से जो इक्ट्ठा किया वह आंकड़े मैं सदन में बताना चाहता हूं । 1999-2000 में चौटाला जी ने 31,018 लाख रुपए डीजल पर वैट टैक्स लगाकर इक्ट्ठे किए थे। 2000-01 में चौटाला जी ने और बी०जे०पी० की सरकार ने 42,902 लाख रुपए डीजल पर वैट टैक्स लगाकर इक्ट्ठे किए थे । 2001-02 में चौटाला जी ने 48,874 लाख रुपए डीजल पर वैट टैक्स लगाकर इक्ट्ठे किए थे । 2002-03 में 53,181 लाख डीजल पर वैट टैक्स लगाकर हरियाणा के किसानों से

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

इक्ट्ठे किए थे । 2003-04 में 71,891 लाख रुपए डीजल पर वैट टैक्स लगाकर चौटाला साहब की सरकार ने इक्ट्ठे किए थे। 2004-05 में 87,673 लाख रुपए वैट टैक्स से इक्ट्ठे किए थे यानि कि कुल 3365 करोड़ 39 लाख रुपए 5 साल में लोकदल और बी०जे०पी० की सरकार ने केवल टैक्स लगाकर हरियाणा के गरीब मजदूर, गरीब किसान और ट्रांसपोर्टरों से इक्ट्ठे किए थे। सर, पैट्रोल पर जो वैट टैक्स लगाया उससे 1433 करोड़ 94 लाख रुपए इन्होंने इक्ट्ठे किए थे। यानि कि पांच साल के अन्दर केवल डीजल और पैट्रोल पर वैट टैक्स से 4799 करोड़ 33 लाख रुपए की कुलैक्शन थी। अध्यक्ष महोदय, लगभग 4800 करोड़ रुपए गरीब किसानों से पांच साल में उनका शोषण करके इक्ट्ठे किए और आज ये गरीबी हटाने की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने आते ही श्रीमती सोनिया गांधी जी से आह्वान किया कि सरकारों को ही टैक्स का प्रतिशत वहन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज गृहणियां सबसे ज्यादा एल०पी०जी० गैस के सिलैंडर का इस्तेमाल करती हैं। मेरी बहन यहां पर बैठी हुई हैं, इसलिए मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि जो 4 प्रतिशत वैट टैक्स लोकदल और बी०जे०पी० की सरकार एल०पी०जी० के सिलैंडर पर लगाती थी उस वैट टैक्स को हरियाणा सरकार ने 6 जून, 2008 से बिल्कुल समाप्त कर दिया है और ऐसा करने वाला हरियाणा ही अकेला ऐसा प्रान्त है जिसने 4 प्रतिशत वैट टैक्स को एल०पी०जी० के सिलैंडर से हटा दिया है। ऐसा करके 52 करोड़ रुपये के करीब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली हरियाणा की सरकार हरियाणा की गृहणियों को सब-सिडी देती है। हमने उस वैट टैक्स को बिल्कुल एबोलिश कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे किसान से डीजल पर 12 प्रतिशत वैट टैक्स लिया जाता था और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने 6 जून, 2008 से उस दर को घटाकर 8.8 प्रतिशत कर दिया है। हमको ऐसा करने से नुक्सान हुआ है। हमको राजस्व का घाटा हुआ है। हमने आपकी तरह 4800 करोड़ रुपए किसानों और गरीबों से नहीं लिए हैं। हमको 2008-09 में लगभग 312 करोड़ रुपए का घाटा डीजल पर वैट की दर कम करने की वजह से हुआ है। स्पीकर साहब, 2009-10 में हमारा अनुमान है कि लगभग 350 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है। यह है एक सोशल वैलफेयर स्टेट, यह है एक गरीब और किसान के प्रति प्रतिबद्धता। अध्यक्ष महोदय, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्या जो यहां मौजूद हैं, को सदबुद्धि दे। इनको और बाकी विपक्ष के साथियों को कम से कम आकंड़ों और फैक्ट्स को फेस करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। उनको कायरों की तरह से सदन से भागना नहीं चाहिए, महज कागज फेंक देने से काम नहीं चलता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी आपस में एक रचनात्मक प्रतिस्पर्धा है, वाद विवाद है। अगर हम गलत होंगे तो हम उसको मानेंगे और यदि वे गलत हों तो उनको भी अपनी गलती को मानकर उसमें सुधार करना चाहिए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान